THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAGANNATH PAHADIA): (a) Yes. Sir.

(b) The Minimum Programme of Action, by the Federation of Indian Chambers of Commerce and industry, contains an analysis of the current economic situation and certain policy suggestions. The salient points made in the study are listed in the statement attached.

(c) Government is seized of the gravity of the economic situation which it has inherited from the previous Government and is determined to tackle it on a priority basis. The proposed measures and the direction of policy in this regard will be presented to this House in due course.

*Statement*

**Note submitted by FICCI on "Minimum programme of Economic Action"**

1. The economic is in a bad shape.

2. There is a need for restoring normal production conditions by better operation of infrastructure enterprises, better utilization of capacity and improved labour discipline.

3. Labour policy needs to be precisely formulated and firmly implemented.

4. Promotion of employment should be achieved by expanded food-for-work programme, rapid expansion in irrigation facilities etc.

5. Prices of mass consumption goods should be stabilised by evolving a dual pricing system and ensuring that prices of essential inputs like coal, electricity etc. are not sharply increased.

6. Controls and regulations of industry and trade should be minimised.

7. Monopolistic role of public enterprises should be reduced and greater role for private enterprises allowed for alround efficiency, in industries including coal, power generation, road transport, steel, etc. and trade both external and domestic.

8. The efficiency of public enterprises should be improved by better management, public vigilance and sub-contacting to private sector.

9. There should be no industrial licensing for investment over Rs. 10 crores even for large houses, except in strategic industry and those in small scale sector; every unit irrespective of size should be allowed automatic expansion upto 30 per cent every 5 years; the concept of "concentration of economic power" should be deleted from the MRTP Act.

10. Incentives should be provided for private investment, including reduction in excise and customs duties, accelerated depreciation, etc. some part of depreciation should be linked to a machinery price index; convertibility clause should be abandoned; banks credit should be liberalised.

11. The rate of corporation tax should be brought down to 50 per cent for all companies, and of personal income tax to 60 per cent, inclusive of compulsory deposit; wealth tax should be abolished.

12. An intensive export drive is needed and export policy should not be formulated on a switch-off switch-on basis.

13. Port deveopment and mechanised handling of goods are imperatives for supporting any worthwhile foreign trade programme.

गुजरात सरकार को खाद्य तेल की सप्लाई

236. श्री छीतूभाई गामित : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1979 से दिसम्बर, 1979 की अवधि के दौरान गुजरात सरकार द्वारा मांग की गई खाद्य तेल की मात्रा कितनी है और केन्द्रीय सरकार द्वारा वस्तुत: सप्लाई की गई खाद्य तेल की मात्रा कितनी है;

(ख) गुजरात सरकार को खाद्य तेल की अपेक्षित मात्रा सप्लाई न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) गुजरात सरकार को खाद्य तेल की सप्लाई के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये अथवा किये जाने वाले ठोस उपायों का ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और इस्पात तथा खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी)** : (क) तथा (ख). शुरू में जून, 1979 में गुजरात सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं में वितरण हेतु 1000 मीटरी टन आयातित तेलों की मांग का अनुमान लगाया था। तथापि, बाद में उन्होंने जुलाई से अक्तूबर, 1979 की अवधि के लिए इस मांग को बढ़ाकर 15,000 मीटरी टन प्रति मास कर दिया। चूंकि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर किये गये आबंटनों के बराबर तेल की मात्रा नहीं उठाई, अतः मंत्रीय तथा अधिकारी दोनों ही स्तरों पर गुजरात सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की गईं। इन बैठकों के दौरान, गुजरात सरकार से अनुरोध किया गया कि वे तेल की मात्रा उठाने के कार्य में तेजी लाएं और उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि राज्य सरकार को आयातित तेलों की आपूर्ति नियमित रूप से की जाती रहेगी, ताकि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मांग को पूरा कर सकें।

गुजरात सरकार के साथ हुए इन विचार-विमर्शों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को जुलाई और सितम्बर, 1979 के बीच 22,000 मीटरी टन पामोलियम और 3300 मीटरी टन आर0बी0डी0 पाम आयल का आबंटन किया गया था। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा अमरीका से उपहार-स्वरूप आयातित दो बार परिष्कृत (डबल रिफाइंड) 17,000 मीटरी टन सोयाबीन का तेल भी गुजरात सरकार के लिए रखा गया।

गुजरात सरकार ने अक्तूबर, 1979 के अंत तक पामोलियम की 17,135 मीटरी टन मात्रा उठाई। नवम्बर-दिसम्बर, 1979 के लिए राज्य सरकार ने कोई अनुमान नहीं लगाये थे। तथापि, राज्य सरकार को बकाया आबंटित मात्रा का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी और उन्होंने नवम्बर, 1979 में 1560 मीटरी टन और दिसम्बर, 1979 में 3600 मीटरी टन मात्रा उठाई। जहां तक आर0बी0डी0 पाम आयल का संबंध है, 3300 मीटरी टन के आबंटन की तुलना में राज्य सरकार ने केवल 1300 मीटरी टन मात्रा उठाई और शेष मात्रा के आबंटन को, उनके ही विशेष अनुरोध पर 19-9-79 को रद्द कर दिया गया। जहां तक दो बार परिष्कृत (डबल रिफाइंड) सोयाबीन के तेल का संबंध है, राज्य सरकार ने जुलाई से सितम्बर, 1979 तक की अवधि के दौरान केवल 3293 मीटरी टन मात्रा उठाई और मिली सूचनानुसार उसके बाद इस तेल की कोई मात्रा नहीं उठाई है।

(ग) जैसा कि राज्य सरकार को पहले ही आश्वस्त किया जा चुका है, केंद्र सरकार द्वारा उनकी आयातित तेल की संपूर्ण मांग को पूरा किया जाता रहेगा। इस प्रयोजन के लिए राज्य व्यापार निगम के साथ पर्याप्त मात्रा में खाद्य तेलों का आयात करने के लिए पहले ही प्रबंध किये जा चुके हैं।

**12.00 hrs.**

## RE: QUESTION OF PRIVILEGE

MR. SPEAKER: As I had mentioned in the House on 30 January, 1980, I had referred the notices of question of privilege regarding reported arrest of Shri N. K. Singh, DIG, CBI, to the Minister of Law, Justice and Company Affairs. A further notice received in the evening on that day from Shri Ram Jethmalani on the same subject was also referred to the Minister of Home Affairs and the Minister of Law.

I am in touch with the Ministers concerned and they have informed me that they are obtaining the requisite information from the Government of Haryana and except to furnish it during the course of the day. Thereafter, I will go urgently into the admissibility of the notices and hope to give the ruling tomorrow.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): After that, I have given another privilege motion against Haryana Chief Minister, Mr. Bhajan Lal.... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: That is under my consideration.

PROF. MADHU DANDAVATE: He has passed derogatory remarks against Parliament in the press conference.... (*Interruptions*)